पूर्ण सुधार आन्दोलन

जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा

वो भारत देश है मेरा

सोने की चिड़िया

http://sonekichidiya.in

एक गर्व करने योग्य भारत[1]

1. **सबकी सुरक्षा और त्वरित न्याय**
2. **भ्रष्टाचार का तीन वर्षों में सम्पूर्ण उन्मूलन**
3. **मुद्रास्फीति से न गिरने वाला सशक्त रुपया**
4. **उत्पादन और व्यापार में आने वाली रुकावटों की समाप्ति**
5. **गरीब से गरीब छात्रों की भी की उत्तमश्रेणी के विद्यालयों तक पहुँच**
6. **गरीबी की तीन वर्षों में समूल समाप्ति**
7. **न्यूनतम कर, जोकि सरकार द्वारा केवल महत्वपूर्ण कार्यों के किये जाने से संभव**
8. **परिवहन, उर्जा और पानी समेत उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाएँ**
9. **चुनाव सुधारों द्वारा अच्छे व्यक्तियों को सामाजिक जीवन में लाने के लिए प्रोत्साहित करना**
10. **किसानों को बेहतरमूल्य जब तक मूल्य नियंत्रण मुक्त न हो जाएं**

हजारों वर्षों तक हमारा विज्ञान, कृषि, और शिल्प कौशल अद्वितीय था। हम रोमन साम्राज्य और यूरोप के लिए जरूरतों तथा विलासिताओं की आपूर्ति करते थे[2]। परिणामस्वरूप भारत दुनिया के अधिकांश सोने का अंतिम गंतव्य था।। इसलिए यह एक सोने की चिड़िया के रूप में देखा जाता था। भारत मानवता के लिए मार्गदर्शक प्रकाश भी था, दुनिया के कई धर्मों और दार्शनिक पद्धतियों का यहाँ पर जन्म हुआ था।

इस गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में, अंग्रेज़ शासन एक बड़ा झटका था जिसने हमें सैंकड़ों वर्ष पीछे धकेल दिया। लेकिन अंग्रेजों के जाने के पैंसठ वर्ष बाद भी, हम शायद ही किसी प्रकार से बेहतर हो पाए हैं। आज का भारत निश्चित रूप से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के सपनों का भारत नहीं है। हम आज गणतंत्र कम और एक तानाशाहों द्वारा शासित दीन राष्ट्र ज्यादा हैं। स्वशासन के छह दशकों के बाद अब हम अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते।हमें भारत के सतत अन्याय, पतन, और भ्रष्टाचार के लिए अपने हिस्से की साझी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब वह समय आ चुका है कि हम वर्तमान परिस्थितियों के सुधार के लिए प्रयत्नशील बनें।

हमारे "माननीय"राजनेताओं ने भारत की दुर्दशा कर हमारे गौरवान्वित देश को उसके घुटनों के पर खड़ा कर दिया है:

---

[1] Draft, 12 February 2013.

[2]Mukund, Kanakalatha, Merchants of Tamilakam: Pioneers of International Trade, Delhi: Allen Lane, 2012. (Series Editor: Gurcharan Das), see Foreword.

- भारत अपने ज्ञान, नवीनता, बुद्धिमत्ता और चरित्र की अपेक्षा अपने व्यापक भ्रष्टाचार के लिए अधिक प्रसिद्ध है। हमारे भ्रष्ट राजनेताओं ने अत्यधिक मात्रा में काला धन संचित कर लिया है जिसका दुरुपयोग सोना और जमीन खरीदने जैसे अनुत्पादक कार्यों में होता है जिससे उत्पादकता कम होती है और राष्ट्रीय चरित्र को क्षति पहुंच रही है।।
- कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है और न्य।य तो लगभग अस्तित्वहीन ही है। यदि नागरिक न्याय की मांग करें तो उन्हें पुलिस की निर्ममता का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर उन राजनेताओं को कोई छू भी नहीं पाता जो दंगे और कत्ल जैसे कुकृत्यों में लिप्त हैं।
- भारत एक दमनकारी पुलिस राज्य है, यहाँ निर्दोष युवक-युवतियों को सोशल-मिडिया पर विचार अभिव्यक्ति करने पर बंदी बना लिया जाता है। रक्षक के रूप में नहीं वस्तुतः हमारी पुलिस रिश्वतखोर के रूप में जानी जाती है।
- बेईमान, भ्रष्ट और आपराधिक तत्व भारत में ऊचाइयों पर पहुँच जाते हैं और ईमानदार लोग या तो दरकिनार कर दिए जाते है, उत्पीड़ित किये जाते है या मार ही डाले जाते हैं।
- हमारा संविधान जोकि सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता के अपवादों से ग्रसित है, और मूलभूत स्वतंत्रता, उदाहरण स्वरुप संपत्ति का अधिकार, के हनन से भरा हुआ है, अम्बेडकर के संविधान की छाया मात्र है।
- सार्वजनिक संपत्ति राजनेताओं ने लूट ली है, अपने स्वार्थ के लिए ये खनिज सम्पदा और खदानों को अपने साथियों को कौड़ियों के मूल्य पर बेच देते हैं।
- गंभीर कर अक्षमताओं (30 से अधिक प्रकार के कर) ने बचत और निवेश पर रोक सी लगा दी है।
- गणतंत्र के दो सम्मानित स्तंभों - न्यायालय और मीडिया - का भी सत्ताधारी दलों और संकीर्ण और भ्रष्ट स्वार्थों के विस्तार का संकट बना हुआ है।
- राजनेताओं ने अपने स्वार्थलाभ और लूट के लिए अभी भी पुराने ब्रिटिश कानूनों, नीतियों और शासन प्रणाली को लागू कर रखा है और वह विश्व की उत्तम व्यवस्थाओं को लागू नहीं करना चाहते हैं। ।
- शासन के बजाय, हमारी सरकारों ने केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में अधिक समय बिताया है, जिससे सरकारें व्यापार में संलग्न रह सकें, और नागरिकों को स्वतंत्र रूप से उत्पादन और व्यापार करने से रोक सकें।

सरकार हमारी नौकर होकर भी मालिक की तरह व्यवहार करती है। काले धन के ढेर पर बैठे हमारे भ्रष्ट राजनेता ब्रिटिश उपनिवेषकों से भी अधिक दमनकारी हैं।

हमारे अधिकाँश प्रतिभाशाली नागरिक विदेशों में बसने के लिये भारत छोड़ रहे हैं क्योंकि इस राष्ट्र में वो अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने में असमर्थ हैं। यह कोई अधिक पुरानी बात नहीं है जब भारत की विश्व के व्यापार में 25 प्रतिशत की भागीदारी थी और अब स्थिति यह है कि वो भागीदारी मात्र 1.2 प्रतिशत की रह गई है। हमारी अर्थव्यवस्था की भागीदारी भी विश्व में 2.7 प्रतिशत ही रह गई है जो पहले एक-तिहाई हुआ करती थी। सूक्ष्म देश जैसे सिंगापुर, मलेशिया और हौंग-कौंग, थोड़े बड़े देश जैसे साऊथ कोरिया, ताईवान, जापान, और बड़े देश जैसे चीन, सभी ने उल्लेखनीय विकास कर लिया है जब कि भारत अभी अत्याचार ग्रसित ज़िम्बॉब्वे और रूस के चोर-तन्त्र से मेल खाता है।

आज की स्थिति मुग़ल साम्राजय के टूटने के समय जैसी है। आज 300 से भी अधिक वर्षों के अन्धकार-पूर्ण समय में बाबा रामदेव और अन्ना हज़ारे के द्वारा काले धन और भ्रष्टाचार के विरोध में वर्ष 2009-2012 के आन्लादोलनों ने देश की ग़हराई तक व्याप्त निराशा को छुआ है और एक ऐसी जाग्रति का संचार किया है जो अब रोकी नहीं जा सकती है।

अब वो समय आ गया है कि इन आन्दोलनों से ना कि अपनी मांगें पूरी करवाई जायें बल्कि यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन की सम्पूर्ण मरम्मत हो, भारत विश्व का सर्वोत्तम राष्ट्र बने और एक बार फिर हम उस पर गर्व कर सकें।

आन्दोलन के लिए आह्वाहन

समय आ गया है की हम जाग जाएँ और अपने राष्ट्र का उत्तरदायित्व अपने कंधो पर लें। "सोने की चिड़िया" आन्दोलन भारतीयों से ये आह्वाहन करता है कि-

1. शासन के नाम पर देश को लूटने वाले निरंकुश शासकों को जड़ से उखाड़ फेंको; और
2. सरकार से स्वतन्त्रता, अच्छे शासन, और उत्तरदायित्व की मांग करो|

हम एक ऐसा भारत चहते हैं जहाँ कोई भी बच्चा, महिला और पुरुष भूखा न हो और न ही असुरक्षित महसूस करे। हम, लोगों की ऊर्जा को स्त्रावित करना चाहते हैं जिससे कि वो भारत को फिर से एक ऐसी धरती बना सकें जो दूध और शहद से भरी हुई हो, ऐसी धरती जहाँ प्रचुर मात्रा में फल और पर्याप्त जल हो, जो फसलों से आच्छादित हो और जहाँ सोने की चिड़िया हर पेड़ हर डाल पर कल्लोल करे।

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम् शस्यशामलां मातरम् । वन्दे मातरम्

नये भारत के लिये प्रस्तावित स्वप्न

हम निम्नलिखित उद्देश्यों का प्रस्ताव करते हैं जिन्हें समय के साथ उन्नत बना सकें। हम एक ऐसा भारत चाहते हैं -

(1) जहाँ सरकारें हमें देश के मालिकों की तरह सम्मान दें।

(2) जहाँ हम अपनी खुशियों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिये स्वतन्त्र हों जबतक की उन लक्ष्यों को पाने में हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएं।

(3) जहाँ हमारे बच्चे महत्वाकांक्षी हों और ये जानते हों कि उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर पारितोषिक मिलेगा न कि उनकी पहुँच के आधार पर।

(4) जहाँ ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जिसमें हर व्यक्ति में अपनी रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त करने की योग्यता हो।

(5) जहाँ समृद्धि अधिकारपूर्ण तरीके से प्राप्त होगी जो कि न ही चोरी होगी और न ही बाँटी जा सके।

(6) जहाँ सभी को, ग़रीब से ग़रीब को भी अपनी क्षमता को पहचानने का समान अधिकार हो:

- ग़रीबों को भ्रष्ट कल्याणकारी योजनाओं पर आश्रित नहीं रहना हो, उन्हें ग़रीबी रेखा से ऊपर लाने के लिये उचित धन सीधे ही हस्तांतरित हो।
- ग़रीबों और अमीरों के बच्चे एक ही विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करें (साथ ही नागरिकों को ये अधिकार हो कि वो शिक्षा के संस्थान बिना सरकार की अनुमति लिये स्वयं ही स्थापित कर सकेंगे परन्तु वो अभिभावकों और छात्रों के प्रति उत्तरदायी हों। और;
- सभी की शीघ्र आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच हो, साथ ही सामाजिक बीमा के द्वारा ग़रीबों की आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच हो।

(7) जहां अपराधियों, लूट-मार करने वाले राजनेताओं, पुलिस कर्मचारियों, और अफसरशाहों से सभी सुरक्षित हों।

(8) जहाँ शीघ्र और समानुपातिक न्याय हो-

- जहाँ जाँच और निर्णय "फास्ट ट्रैक" गति के साथ हों;
- न्यायालय शीघ्रता के साथ निष्कपट और निष्पक्ष न्याय दें; और
- भ्रष्ट तरीकों से उपार्जित संपत्ति ज़ब्त हो।

(9) जहाँ गुंडे और अपराधी MP या MLA नहीं बन सकते-

- सिर्फ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति ही चुनावों में भाग ले सकें और अस्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों को चुनावों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाए; और

यदि फिर भी कोई अपराधिक तत्व नियुक्त होता है तो उसे शीघ्र सुनवाई के साथ पद से हटा दिया जाए|

(10) जहाँ सरकारी अफसर पूर्णतः उत्तरदायी होंग, भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो चुका हो और काला धन घोषित हो और वापस लाया जाए|

(11) जहाँ नागरिक बिना राज्य के नियन्त्रण के उत्पादन और व्यापार करने में सक्षम हों:

- अतः हम हर चुंगी पर रुके बिना वस्तुओं का परिवहन कर सकें; और
- वैश्विक व्यापार करें जो कि हमारे राष्ट्र का के एक महान व्यापारी राष्ट्र के रूप के संगत हो।

(12) जहाँ हमारी ज़मीन सुरक्षित हो:

- जहाँ हम बिना भ्रष्ट साधन अपनाये हुए ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख्त कर सकें
- जहाँ सरकार हमारी ज़मीनों को बलपूर्वक छीनकर बड़े व्यवसायियों को नहीं दे सके।

(13) जहाँ सरकार स्वच्छ जल, पर्याप्त सड़कें, ऊर्जा, बन्दरगाह और रेलमार्ग, और अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं को सुगम बनाएगी|

(14) जहाँ सरकार अपने संसाधनों के भीतर रहकर ही शासन करे, कर कम हों, ऋण चुकाया जा चुका हो और मुद्रास्फीति से हमारी मुद्रा का मूल्यहीन न हो।

हमें यह कैसे पता चलेगा कि हम सफल हुए हैं?

हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं जब सुरक्षा, न्याय, स्वतंत्रता (जवाबदेही के अधीन), शिक्षा और स्वास्थ्य, और महिलाओं की स्थिति में तेजी से वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार, सामाजिक उत्पीड़न और भेदभाव अतीत की बात बन जाएगा । इसके अतिरिक्त, हम जान पाएँगे कि हम सही दिशा में हैं, जब हर कोई अधिक समृद्ध हो होगा, और गरीबी इतिहास बन जाएगी।

आज के अराजकता और भ्रष्टाचार को देखते हुए, भारत के सबसे प्रतिभाशाली नागरिक, विदेशी दूतावासों के सामने कतार लगाकर, स्थायी रूप से भारत छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न केवल हम इन कतारों को उल्टा करना चाहते हैं, बल्कि हमें पता चलेगा कि हम सफल हुए हैं जब दुनिया के सबसे अच्छे स्नातक भारत आने को लालायित हो जाएँ, और वो भारतीय जोकि पहले जा चुके हैं वापस लौटें क्योंकि विश्व भारत को अब एक ऐसे देश के रूप में देख रहा है, जहाँ स्वतंत्रता, सम्भावना, विज्ञान, ज्ञान, आध्यात्मिकता और अखंडता है, जैसा कि यह देश पूर्व में था।

सुशासन के सिद्धांत

इस उद्देश्य को एक वास्तविकता बनने के लिए, सरकार को निम्न आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए:

1) लोकतंत्र और विकेन्द्रीकरण

लोकतंत्र अल्पसंख्यक को दबाने का लाइसेंस नहीं है: लोकतंत्र सार्वजनिक बहस और निर्णय लेने का एक उपकरण है और अपने आप में एक अंत नहीं है। लोकतंत्र पर इस बात का संवैधानिक नियंत्रण होना चाहिए जो कि अल्पसंख्यकों पर अनुचित अधिरोपण या उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाने से रोके। हम विश्वास करते हैं कि सभी शक्तियों को, अतिरिक्त उनके जो स्पष्ट रूप से राज्य को सौंपी गयी हैं, व्यक्ति (और परिवार) के साथ रहना चाहिए। यह भी विकेन्द्रीकरण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा व्यक्ति संप्रभु है, जहाँ कुछ शक्तियों स्थानीय प्रशासन को, कुछ राज्य सरकार को और सबसे कम केंद्र को दी गयी हैं। सही मायनों में स्वराज केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार के कार्यों का सबसे निचली इकाइयों जैसे गाँव या मोहल्ला द्वारा किया जाए।

जहाँ ऐसे प्रत्यायोजन को प्रभावशीलता के हित में लागू किया गया है वहां इनके दुरूपयोग को रोकना चाहिए (उदाहरण स्वरुप: खाप पंचायत) और कानून के शासन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के स्थानीय निकायों को, उत्तरदायित्व के अधीन, कर (दरें) और उपकर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए जिससे कि वे स्थानीय निर्णयों जैसे कि आधारभूत सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें।

2) सुदृढ़ उत्तरदायित्व तंत्र

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए की सरकार उच्च अखंडता और सक्षमता वाले लोगों को नियुक्त करे और उन्हें अच्छा पारिश्रमिक दे (बाज़ार मूल्यों के अनुसार)। सरकार को, विशेष रूप से, चुनाव सुधारों के मध्यम से उल्लेखनीय प्रोत्साहन देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे की धूर्त, दोषी, और भ्रष्ट लोगों को तंत्र में आने से हतोत्साहित करे। सभी वर्गों लोक सेवकों को परिणाम देने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। उपलब्धि पुरस्कृत होनी चाहिए और अपालन (सही प्रदर्शन न करने पर) (नागरिकों से प्रदर्शन के फ़ीडबैक के आधार पर) को बिना सूचना के निष्काषित किया जाना चाहिए। कार्यकालिक सेवाओं जैसे कि IAS को अनुबंधात्मक सेवाओं से बदलना चाहिए जिसमें की गैर प्रदर्शन का निष्कासन और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए।

3) सरकार को अपनी मूल भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छी तरह करना चाहिए

सरकार की मुख्य भूमिका रक्षा और पुलिस (सुरक्षा) और न्याय है। न्याय आसानी से माँगा जाने वाला, शीघ्रगामी, और मिलते हुए दिखना चाहिए। सरकार को सभी अपराधियों, हत्यारों और भ्रष्ट लोगों को पकड़ना चाहिए और दण्डित करना चाहिए ।

4) अपनी मूल भूमिका को ठीक से करने के बाद सरकार कुछ अतिरिक्त कार्य कर सकती है

एक सरकार के लिए एक व्यापारी की भूमिका ले लेना बहुत खतरनाक है। एक प्राचीन भारतीय कहावत के अनुसार: जहाँ का राजा हो व्यापारी वहाँ की प्रजा हो भिखारी। हम इस संभावना पर विचार करते हैं कि सरकार अपने बहुत से वर्तमान कार्यों से बाहर आएगी और विश्व की सर्वोच्च नीति के आधार पर नए कार्यों पर विचार करेगी जो यह परीक्षण करते हैं सुनियोजित करती हैं कि क्या सरकार की भूमिका है, क्या यह पूर्ण लाभ दे सकती है।

सुरक्षा और न्याय को उपलब्ध कराने के बाद सरकार सशक्त रूप से एक आधारभूत संरचना प्रदान कर सकती है जो कि निजी उद्यम द्वारा नहीं बनाए जा सकते और नागरिकों को समान अवसर के द्वारा उनकी क्षमता (योग्यता के आधार पर) को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। सरकारी कार्यों में इस तरह के बदलाव करने से परिणामतः सार्वजनिक सेवा सुरक्षा (पुलिस, रक्षा) और न्याय में नौकरियां बढ जाएंगी जबकि कई अन्य रोजगार के अवसर कम हो जाएँगे।

5) परिवर्तनकालीन व्यवस्थाएं

यह महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन विघटनकारी न होकर समुचित समायोजित हो जिससे कि भ्रष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी को हानि न हो। इसका अर्थ यह हो सकता है कि जब तक मूल्य पूर्णरूप से स्वतंत्र न हों, कुछ राजसहायताएँ (सब्सिडी) कुछ समय के लिए चलन में रहें, और किसानों को प्रत्यक्ष मूल्य चुकाया जाए ।

नए भारत के मूल्य

खुली बहस और सम्मानित निष्कर्ष की प्राचीन भारतीय परंपरा पर आधारित राष्ट्रीय निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत हमें हमारे उस भारत के निर्माण में सहायता कर सकता है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं -

1) समग्र भारत

भारत एक राष्ट्र है। सनकपन नहीं, क़ानून का शासन लागू होना चाहिए। सरकार को हर नागरिक को, किसी भी जन्मजात या समूह विशेषता के संदर्भ में, जैसे लिंग या धर्म या जाति, के बिना एक जैसा समझना चाहिए। कोई भी सामजिक सुरक्षा राशि सम्बंधित निर्णय जाति या धर्म को आधार ना मानकर पूर्णतया आर्थिक होना चाहिए ।

2) समान अवसर

हम विश्वास करते हैं कि मुक्त समाज में सभी को समान अवसर (मूलतः शिक्षा) मिलने चाहिए। इसमें गरीबी को दूर करना भी सम्मिलित है।

3) प्रत्येक व्यक्ति भारत की नींव है

सभी स्त्री और पुरुष अद्वितीय हैं और समाज का आधार बनाते हैं। हम जानते हैं कि लोगो की प्रगति, कल्याण और प्रसन्नता उनके उद्यम, पहल और ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों और शिक्षा के माध्यम से, दूसरों के साथ कार्य करके और सेवा करके हम अपनी सामर्थ्य के अनुरूप कार्य करके स्वयं और समुदाय के लिए उत्तम परिणाम लाते हैं। देश को प्राथमिकता किसी व्यक्ति के मूल्य पर नहीं दी जानी चाहिए।

4) प्रमुख सामाजिक इकाई के रूप में परिवार

हम परिवार की, नई पीढ़ी को आगे लाने में और उन मूल्यों को आत्मसात कराने में जो एक व्यक्ति को आत्मसामर्थ्य होने का अहसास दिलाता है और समाज को सर्वोच्चता पर ले जाता है , इस भूमिका को समझते हैं और महत्व देते हैं। मूलतः हम महान भारत के निर्माण में माताओं ,भगिनियों और पुत्रियों की भूमिका की महत्व देते हैं ।

उच्च प्रजनन क्षमता प्रायः निराशा, गरीबी का एक लक्षण है। जैसे-जैसे-लोग धनी होते हैं और इस बात की आशा करने लगते हैं कि अगर उनके बच्चे शिक्षित होते हैं तो वे उसने भी अधिक उप्लब्धियाँ प्राप्त करेंगे, जनन क्षमता गिरने की ओर अग्रसर होती जाती है। सही शिक्षा और प्रेरणा की सहायता से हमारी विशाल जनसंख्या प्रचुर संपत्ति का उत्पादन करेगी। जैसे जैसे अच्छी नीतियों को लागू किया जाएगा हम आशा करते हैं कि, जन्म दर में तेजी से गिरावट आएगी क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश को अधिक उपयोगी पाएँगे।

5) आध्यात्मिक और भौतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता

प्रत्येक भारतीय को अपनी भौतिक और/या आध्यात्मिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जो दोनों मिलकर भारत की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बनाते हैं।

यतो भ्युद्यानी श्रोय्से सिद्धि: स धर्म:[3]

हम राज्य के उसके अनुबंधों को लागू करने, और ऐसे व्यक्तिओं को रोकने और दण्डित करने की कटिबद्धता और राज्य के द्वारा व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता और न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत के साथ हैं।
ऐसे मामलों में सरकार, जो कि हमारी सेवक है, हमें यह नहीं बोल सकती कि हमें कैसे जीना चाहिए या हमें कोन से विकल्प चुनने चाहिए। सरकार की भूमिका केवल हमें दूसरों को हानि पहुँचाने से रोकने तक ही सीमित है।

---

[3] वेदों में यह कहा गया है कि जब व्यक्ति केवल भौतिक संसार में प्रवेश करता है तो वह अंधकार में प्रवेश करता है, पर समानरूप से जब कोई केवल आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करता है तो वह तब भी केवल अंधकार में ही प्रवेश करता है। केवल वह जो दोनों का वरण करता है तीनों लोकों का पार पाता है।

6) स्वतंत्रता उत्तरदायित्व के साथ आती है

स्वतंत्रता उत्तरदायित्व के साथ आती है(कर्मफल सिद्धांत)। यह भारत की सभी वैचारिक प्रणालियों का मूलभूत सिद्धांत है। स्वतंत्रता दूसरों को हानि पहुचाने के लिए नहीं है। उत्तरदायित्व मनुष्य तक सीमित नहीं है । बल्कि पशुओ को भी बिना दर्द के जीने करने का अधिकार है। विशेषरूप से, जहाँ जानवरों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए और प्रयास किया जाना चाहिए ही उन्हें कम से कम पीड़ा हो। इसके अतिरिक्त, पादप विविधता बनाए रखी जानी चाहिए, विशेष रूप से अत्यधिक औषधीय गुणों से युक्त पौधों की, और प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक रूप से दोहन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आत्म हानि के बारे में क्या? जीवन में बहुत सारी चीजे हमें अधिकता में या कम मात्रा में हानि पहुँचा सकतीं हैं। लेकिन जैसा कि गांधी ने कहा, " वह स्वतंत्रता किस योग्य है जहाँ गलतियाँ करने की स्वतंत्रता नहीं है"। हम विश्वास करते हैं कि सार्वजनिक मर्यादा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए नियमों के अलावा, हर व्यक्ति को गलतियों को करने के लिए और उनसे सीखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। हम अपने मित्रों और परिवार के मार्गदर्शन बल्कि सामाजिक सुधार की वकालत के लिए भी जिम्मेदार हैं। लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है की सरकार, जो की हमारी सेवक है, की आक्रामक शक्तियों का निजी मूर्खता के निषेध के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

7) सत्य और वैज्ञानिक पद्धति

एक शक्तिशाली प्राचीन भारतीय उक्ति कहती है “सत्यमेव जयते”, जिसका अर्थ है कि सत्य की विजय होती है । सत्य को नए विचारों के खुलेपन की (आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः - शुभ विचारों को हर दिशा से आने दो - ऋग्वेद 1 -89-1) ,और वाद विवाद के खुलेपन की आवश्यता होती है। वैज्ञानिक पद्धति जिसका मूल प्राचीन भारतीय विज्ञान है, सत्य को खोजने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है । तदनुसार हमें आशा है “सोने कि चिड़िया” आन्दोलन में प्रतिभागियों के बीच अपरिहार्य मतभेद वास्तविक वाद विवाद और सत्य की खोज पर आधारित होंगे।

8) विविधता और सहिष्णुता

हम विचार और विश्वास की विविधता, और एक सहिष्णु भारत को महत्व देते हैं। निश्चय ही, स्वदेशी भारतीय सोच में सभी आधुनिक प्रणालियों की संयुक्त विविधता से अधिक विविधता थी। हम जीन पियरे लेहमेन से सहमत हैं कि "एक वैश्विक वातावरण जो की विचारों, दर्शन और धर्म के लिए आतुर है, भारत तीनों का सबसे उर्वर जन्मस्थान है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र और विविधता का महान तालमेल है। इस ग्रह को मूल्यों, आध्यात्मिकता और एक नैतिक दिक्सूचक की आवश्यकता है। भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराए इन तीनों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं।

9) व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता

भारत हजारों साल तक एक महान मुक्त बाजार (श्रम, माल, सेवाओं, और पूंजी में) था। पूरा विश्व खरीदने और बेचने के लिए भारत के किनारों पर आया। हम व्यवसाय की स्वतंत्रता और व्यापार की योग्यता को महत्व देते हैं। निः शुल्क कृषि उत्पादों की बिक्री विशेष रूप से हमारे कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। शायद यह वह अवसर है जहां व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता पर सवाल उठाया जा सकता है, जब भारत में उत्पादन की लागत से कम मूल्य पर सामान का ढेर लगा दिया जाता है। फिर भी भारतीयों के लिए, गुणवत्ता और कीमत के आधार पर मुक्त विकल्प, उन बाधाओं को जो भारत की दूरगामी प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकती हैं, आरोपित करने से ज्यादा अच्छा है। स्वतंत्रता के 65 वर्षो बाद, किसी भी परिस्थिति में, 'शिशु उद्योग' तर्क का उपयोग युक्तिसंगत नहीं है।

एक समाज जो इन सिद्धांतो का पालन करता है, स्वयं और इस वातावरण के साथ परस्पर सद्भावना के साथ रह सकता है। शायद इन आकांक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए एक उपयोगी अभिव्यक्ति “आध्यात्मिक न्यायवाद” है।